Test Cloud

# Daily करेंट अफेयर्स

11 - 12 अगस्त 2025

## NATIONAL AFFAIRS

### 1. सरकार ने PM E-DRIVE योजना को दो वर्ष बढ़ाकर मार्च 2028 तक कर दिया।

भारत सरकार ने PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (PM E-DRIVE) योजना के दो साल के विस्तार की घोषणा की है, जिससे इसकी वैधता 31 मार्च, 2026 से बढ़कर 31 मार्च, 2028 हो गई है। इस विस्तार का उद्देश्य 10,900 करोड़ रुपये के मूल बजट आवंटन को बनाए रखते हुए, इलेक्ट्रिक बसों, ट्रकों और एम्बुलेंस सहित सार्वजनिक और आवश्यक सेवाओं में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को अपनाना है।

- **भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) ने पुष्टि की है कि PM E-DRIVE योजना अब 31 मार्च, 2028 को या आवंटित ₹10,900 करोड़ के बजट के पूरी तरह से उपयोग होने तक समाप्त हो जाएगी। यह विस्तार इलेक्ट्रिक बसों, ट्रकों, एम्बुलेंस और सार्वजनिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित है।**

- **विस्तारित समय-सीमा के बावजूद, सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस योजना के लिए कोई अतिरिक्त वित्तीय संसाधन आवंटित नहीं किए जाएँगे। मौजूदा बजट का उपयोग लंबित परियोजनाओं को पूरा करने और निर्दिष्ट क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों को निरंतर अपनाने में सहायता के लिए किया जाएगा।**

- **यह विस्तार इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों (e-2Ws), इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों (e-3Ws), पंजीकृत ई-रिक्शा और ई-कार्ट के लिए सब्सिडी पर लागू नहीं होगा। मूल योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, इन श्रेणियों के लिए प्रोत्साहन 31 मार्च, 2026 को समाप्त हो जाएँगे। विस्तारित योजना का उद्देश्य भारी-भरकम ईवी क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना है, जिनमें उच्च प्रारंभिक लागत, सीमित चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और संचालन एवं रखरखाव में विशेष कौशल की आवश्यकता शामिल है। योजना की वैधता बढ़ाकर, सरकार इन क्षेत्रों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करना चाहती है।**

**Key Points:-**

(i) इस योजना के बजट का एक बड़ा हिस्सा सार्वजनिक चार्जिंग बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए आवंटित किया गया है। सरकार देश भर में इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग की पहुँच और सुविधा को बढ़ाने के उद्देश्य से इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पर्याप्त संख्या में फ़ास्ट चार्जर लगाने की योजना बना रही है।

(ii) आवंटित धनराशि का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए विस्तारित योजना के कार्यान्वयन पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। गृह स्वास्थ्य मंत्रालय चल रही परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि योजना के उद्देश्य विस्तारित समय-सीमा के भीतर पूरे हों।

(iii) PM E-DRIVE योजना का दो साल का विस्तार भारत में, विशेष रूप से सार्वजनिक और आवश्यक सेवा क्षेत्रों में, इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेज़ी लाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मूल बजट को बनाए रखते हुए, इस विस्तार का उद्देश्य क्षेत्र-विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करना और बढ़ते EV पारिस्थितिकी तंत्र को सहारा देने के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचे के विकास को बढ़ावा देना है।

## 2. इंडियाएआई और नेशनल कैंसर ग्रिड ने कैंसर उपचार में एआई नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कैच अनुदान कार्यक्रम शुरू किया।

अगस्त 2025 में, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (DIC) और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अंतर्गत इंडियाएआई इंडिपेंडेंट बिज़नेस डिवीज़न (IndiaAI IBD) ने भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) द्वारा स्थापित राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड (NCG) के साथ मिलकर कैंसर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी चैलेंज (CATCH) अनुदान कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में कैंसर देखभाल में सुधार के लिए AI-संचालित नवाचारों को बढ़ावा देना है।

- **CATCH अनुदान कार्यक्रम का उद्देश्य कैंसर स्क्रीनिंग, निदान, उपचार सहायता और समग्र स्वास्थ्य सेवा संचालन को बेहतर बनाने पर केंद्रित कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) समाधानों के विकास और कार्यान्वयन में तेज़ी लाना है। AI का लाभ उठाकर, यह पहल पूरे कैंसर देखभाल पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत बनाने और देश भर में रोगियों के लिए परिणामों और पहुँच में सुधार लाने का प्रयास करती है।**

- **IndiaAI और नेशनल कैंसर ग्रिड द्वारा सह-वित्तपोषित, यह कार्यक्रम पायलट चरण के दौरान प्रत्येक परियोजना के लिए ₹50 लाख (भारतीय रुपये पचास लाख) तक की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। नैदानिक संस्थानों के साथ काम करने वाले प्रौद्योगिकी नवप्रवर्तकों सहित चयनित टीमों को कैंसर देखभाल चुनौतियों के अनुरूप स्केलेबल AI समाधान विकसित करने के लिए यह धनराशि प्रदान की जाएगी।**

- **सफल पायलट परियोजनाएँ व्यापक NCG नेटवर्क में व्यापक कार्यान्वयन के लिए IndiaAI से ₹1 करोड़ (भारतीय रुपये एक करोड़) तक की अतिरिक्त धनराशि के लिए पात्र होंगी। इस विस्तारित सहायता का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर सिद्ध AI नवाचारों को अपनाने में सुविधा प्रदान करना है, जिससे कैंसर उपचार सुविधाओं में व्यापक पहुँच और प्रभाव सुनिश्चित हो सके।**

**Key Points:-**

(i) CATCH चैलेंज कई प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है जैसे AI-सक्षम स्क्रीनिंग, डायग्नोस्टिक सहायता, नैदानिक निर्णय समर्थन, रोगी जुड़ाव उपकरण, परिचालन दक्षता में वृद्धि, अनुसंधान और डेटा क्यूरेशन।

(ii) पात्र प्रतिभागियों में स्टार्टअप, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी फर्म, शैक्षणिक संस्थान और सार्वजनिक और निजी दोनों अस्पताल शामिल हैं, जो इस महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा चुनौती में योगदानकर्ताओं के विविध समूह को प्रोत्साहित करते हैं।

## 3. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मेरिट योजना के लिए 4,200 करोड़ रुपये के बजटीय समर्थन को मंजूरी दी।

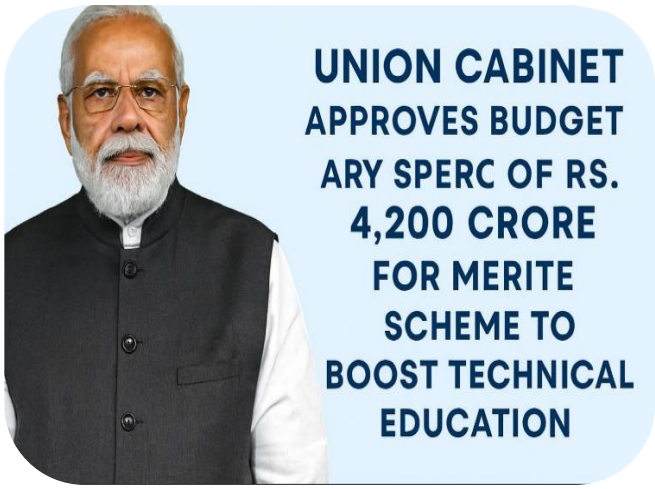


8 अगस्त, 2025 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय क्षेत्र योजना (CSS) - बहु-विषयक शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा में अनुसंधान सुधार (MERITE) योजना के कार्यान्वयन को मंज़ूरी दे दी। यह योजना इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलिटेक्निक सहित 275 तकनीकी संस्थानों को लक्षित करती है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप गुणवत्ता, समानता और शासन को बढ़ाना है।

- **MERITE योजना 275 तकनीकी संस्थानों में लागू की जाएगी, जिनमें 175 इंजीनियरिंग कॉलेज और 100 पॉलिटेक्निक शामिल हैं। यह तकनीकी शिक्षा के मानकों में सुधार के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है, जिसकी अवधि 2025-26 से 2029-30 तक है।**

- **इस योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 4,200 करोड़ रुपये है, जिसमें से 2,100 करोड़ रुपये विश्व बैंक से ऋण के रूप में प्राप्त होंगे। यह धनराशि बुनियादी ढाँचे के विकास, डिजिटल परिवर्तन और शैक्षणिक उत्कृष्टता पर केंद्रित होगी।**

- **इस योजना के तहत, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NITs), राज्य इंजीनियरिंग संस्थान, पॉलिटेक्निक और संबद्ध तकनीकी विश्वविद्यालय (ATUs) जैसे 275 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त तकनीकी संस्थानों का चयन किया जाएगा, जिससे लगभग 7.5 लाख छात्र लाभान्वित होंगे।**

**Key Points:-**

(i) MERITE योजना तकनीकी शिक्षा क्षेत्र को संभालने के लिए जिम्मेदार राज्य और केंद्र शासित प्रदेश (UT) विभागों को भी सहायता प्रदान करेगी, जिससे वे सुधारों और आधुनिक शैक्षिक प्रथाओं को लागू करने में सक्षम होंगे।

(ii) योजना के प्रमुख परिणामों में भाग लेने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में डिजिटलीकरण रणनीतियों को अपनाना, बहु-विषयक कार्यक्रमों के लिए दिशानिर्देशों का विकास, बेहतर रोजगार कौशल और उच्च अध्ययन या रोजगार में छात्रों की संक्रमण दर में वृद्धि शामिल है।

(iii) मजबूत अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देकर, MERITE योजना का उद्देश्य एक उन्नत शिक्षण वातावरण स्थापित करना, उद्योग-अकादमिक सहयोग को प्रोत्साहित करना और एक कुशल और नवाचार-संचालित कार्यबल के भारत के दीर्घकालिक दृष्टिकोण में योगदान करना है।

## 4. कैबिनेट ने असम और त्रिपुरा के लिए 4,250 करोड़ रुपये के विशेष विकास पैकेज को मंजूरी दी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम और त्रिपुरा के लिए विशेष विकास पैकेज (SDPs) की केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत चार नए घटकों को मंजूरी दी है। इन पैकेजों का उद्देश्य

लक्षित बुनियादी ढाँचे और सामाजिक-आर्थिक परियोजनाओं के माध्यम से शांति, पुनर्वास और समावेशी विकास को बढ़ावा देना है।

**• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8 अगस्त, 2025 को इन घटकों को मंज़ूरी दी और इसके लिए कुल 4,250 करोड़ रुपये का केंद्रीय परिव्यय आवंटित किया, जिसमें असम सरकार 3,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त योगदान देगी। इस प्रकार, नए घटकों का कुल वित्तीय भार 7,250 करोड़ रुपये हो जाता है।**

**• यह मंज़ूरी बोडो और कार्बी समूहों के लिए समझौता ज्ञापन (MoS)-आधारित पिछली पहलों की सफलता के बाद दी गई है, जिसके परिणामस्वरूप असम में शांति में सुधार हुआ और विकास में तेज़ी आई। नए घटक इन लाभों को समेकित करने और अन्य समुदायों तक लाभ पहुँचाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।**

**• असम के लिए तीन घटकों को मंजूरी दी गई है, जिनका कुल आवंटन पाँच वर्षों (2025-26 से 2029-30) के लिए 4,000 करोड़ रुपये होगा। ये परियोजनाएँ लक्षित जिलों और समुदायों में बुनियादी ढाँचे, संपर्क और सामाजिक कल्याण को बढ़ाने पर केंद्रित होंगी।**

**Key Points:-**

(i) आदिवासी अवसंरचना पहल के अंतर्गत असम के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में विकास के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक सेवाओं और सामुदायिक सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

(ii) दिमासा सामुदायिक अवसंरचना परियोजना को उत्तरी कछार पर्वतीय स्वायत्त परिषद (NCHAC) क्षेत्रों में विकास के लिए 500 करोड़ रुपये मिलेंगे। इस पहल को दिमासा राष्ट्रीय मुक्ति सेना (DNLA) और दिमासा जनवादी सर्वोच्च परिषद (DPSC) के सदस्यों द्वारा संघर्षोत्तर पुनर्वास प्रक्रिया के एक भाग के रूप में क्रियान्वित किया जाएगा।

(iii) 3,000 करोड़ रुपये की सहायता से उल्फा-प्रभावित क्षेत्र अवसंरचना घटक, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ़ असम (ULFA) के साथ 2023 के MoS पर आधारित है और संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में व्यापक अवसंरचना विकास पर केंद्रित है। इसके अतिरिक्त, त्रिपुरा के लिए, चार वर्षों की अवधि (2025-26 से 2028-29) में लक्षित विकास के लिए 250 करोड़ रुपये का एक अलग आवंटन स्वीकृत किया गया है।

## 5. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PMUY के लिए सब्सिडी जारी रखने, तमिलनाडु में तेल विपणन कंपनियों और सड़क परियोजना को 30,000 करोड़ रुपये का मुआवजा देने को मंजूरी दी।

8 अगस्त 2025 को, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के तहत सब्सिडी जारी रखने, तेल विपणन कंपनियों (OMCs) को मुआवजा और तमिलनाडु में एक सड़क बुनियादी ढांचा परियोजना सहित प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी।

**• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 (वित्त वर्ष 2026) के दौरान PMUY लाभार्थियों के लिए लक्षित सब्सिडी जारी रखने को मंज़ूरी दे दी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) कम आय वाले परिवारों के लिए सस्ती**

**बनी रहे। इस निर्णय का उद्देश्य वैश्विक ऊर्जा कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद LPG अपनाने की दर को बनाए रखना है।**

**• स्वीकृत योजना के तहत, प्रत्येक पात्र परिवार को 14.2 किलोग्राम (किग्रा) के एलपीजी सिलेंडर पर सालाना नौ बार रिफिल तक 300 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। 5 किलोग्राम के छोटे एलपीजी सिलेंडरों के लिए, सब्सिडी राशि क्षमता के आधार पर आनुपातिक रूप से समायोजित की जाएगी। इस योजना पर कुल 12,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे।**

**• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की तीन प्रमुख तेल विपणन कंपनियों (OMCs) को विनियमित कीमतों पर घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति में हुई हानि के लिए 30,000 करोड़ रुपये के मुआवजे को भी मंजूरी दी। लाभार्थियों में नई दिल्ली स्थित इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL), मुंबई स्थित भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) और मुंबई स्थित हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) शामिल हैं।**

**Key Points:-**

(i) यह क्षतिपूर्ति पैकेज तेल विपणन कंपनियों को नियंत्रित LPG मूल्य निर्धारण के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान की भरपाई करने और उनकी परिचालन स्थिरता को सहारा देने के लिए तैयार किया गया है। यह धनराशि महत्वपूर्ण खर्चों को पूरा करने में मदद करेगी और पूरे भारत में घरेलू उपभोक्ताओं को निर्बाध LPG आपूर्ति सुनिश्चित करेगी।

(ii) इसके अलावा, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने तमिलनाडु में मरक्कनम और पुदुचेरी के बीच 46 किलोमीटर लंबे चार-लेन मार्ग के निर्माण को मंज़ूरी दे दी है। यह मार्ग रणनीतिक पूर्वी तट सड़क नेटवर्क का हिस्सा है, जो कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय व्यापार क्षमता को बढ़ाएगा।

(iii) सड़क परियोजना का विकास हाइब्रिड एन्युइटी मोड (HAM) के तहत किया जाएगा, जिसकी कुल लागत 2,157 करोड़ रुपये होगी, जिसमें निर्माण के लिए आवंटित 1,118 करोड़ रुपये और भूमि अधिग्रहण के लिए 442 करोड़ रुपये शामिल हैं। इस परियोजना का उद्देश्य तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देना, रसद में सुधार करना और बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करना है।

## 6. DARPG ने NeSDA के तहत ई-सेवाओं में सुधार के लिए RTS आयुक्तों के साथ सहयोग किया और NAEG 2026 के लिए दिशानिर्देशों की घोषणा की।

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने 5 मार्च, 2025 को आयोजित प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री के निर्देशों के बाद, डिजिटल सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए हाल ही में 10 राज्यों के सेवा के अधिकार (आरटीएस) आयुक्तों के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत किया है।

**• DARPG ने ई-गवर्नेंस में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए 23वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार (NAEG) 2026 के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए।**

**• मार्च 2025 में, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) ने API तकनीक का उपयोग करके RTS पोर्टलों को केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) के साथ एकीकृत करना शुरू किया। रिवर्स इंटीग्रेशन के परीक्षण के लिए हरियाणा को**

**पायलट राज्य के रूप में चुना गया था, जिसका उद्देश्य CPGRAMS से शिकायतों को सीधे RTS पोर्टलों पर मैप करके शिकायत निवारण में सुधार करना था।**

**• 2019 में शुरू किया गया राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन (NeSDA), सात क्षेत्रों में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा ई-सेवा वितरण का मूल्यांकन करता है। 2024-25 की NeSDA रिपोर्ट डिजिटल गवर्नेंस में सुधारों और चुनौतियों पर प्रकाश डालती है, और सेवा संवर्धन का रोडमैप प्रस्तुत करती है।**

**Key Points:-**

(i) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के DARPG ने 1 सितंबर से 15 अक्टूबर, 2025 तक NAEG 2026 के लिए नामांकन खोले हैं। 1 जुलाई, 2023 और 30 जून, 2025 के बीच संचालित परियोजनाएं पात्र हैं, जो नवीन, नागरिक-केंद्रित डिजिटल सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करती हैं।

(ii) NAEG 2026 सरकारी प्रक्रिया पुनर्रचना, AI नवाचार, साइबर सुरक्षा, जिला-स्तरीय पहल और डेटा विश्लेषण जैसी श्रेणियों में 10 स्वर्ण और 6 रजत पुरस्कार प्रदान करेगा। पुरस्कार समारोह नई दिल्ली में मंत्री श्री जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा।

(iii) स्वर्ण पुरस्कार विजेताओं को ₹10 लाख और रजत पुरस्कार विजेताओं को ₹5 लाख, ट्रॉफी और प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएँगे। ये प्रोत्साहन प्रभावशाली लोक सेवा परियोजनाओं के विस्तार और संसाधन संवर्धन में सहायता करते हैं, जिससे भारत के ई-गवर्नेंस लक्ष्यों को आगे बढ़ाया जा सके।

## BANKING & FINANCE

### 1. RBI ने नियामक उल्लंघनों के लिए ICICI बैंक पर 75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

7 अगस्त, 2025 को, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने संपत्ति मूल्यांकन और चालू खाते खोलने से संबंधित नियामक दिशानिर्देशों का पालन न करने के लिए ICICI बैंक लिमिटेड पर ₹75 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया। यह जुर्माना पर्यवेक्षी मूल्यांकन (ISE 2024) के लिए एक वैधानिक निरीक्षण के बाद लगाया गया, जिसमें 31 मार्च, 2024 तक बैंक की वित्तीय स्थिति की जाँच की गई।

**• RBI के निरीक्षण से पता चला कि ICICI बैंक कुछ बंधक ऋणों के मामलों में स्वतंत्र, RBI-अनुमोदित मूल्यांकनकर्ताओं के माध्यम से संपत्ति का मूल्यांकन कराने में विफल रहा। इसके अतिरिक्त, बैंक ने मौजूदा नियामक दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए चालू खाते खोले या बनाए रखे। इन चूकों को इतना गंभीर माना गया कि उन पर मौद्रिक जुर्माना लगाया जाना उचित था।**

**• यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत लगाया गया है।**

**Key Points:-**

(i) RBI ने ज़ोर देकर कहा कि यह कार्रवाई पूरी तरह से नियामक अनुपालन में कमियों के आधार पर की गई है और ICICI बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता को प्रभावित नहीं करती है। इसके अलावा, RBI ने स्पष्ट

किया कि यह जुर्माना बैंक के खिलाफ आगे शुरू की जाने वाली किसी भी पर्यवेक्षी या प्रवर्तन कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

(ii) यह कदम बैंकिंग क्षेत्र में नियामक मानदंडों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। यह वित्तीय संस्थानों को स्थापित दिशानिर्देशों, विशेष रूप से संपत्ति मूल्यांकन और चालू खातों के प्रबंधन के संबंध में, के अनुपालन के महत्व की याद दिलाता है।

(iii) आरबीआई के सक्रिय दृष्टिकोण का उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली की अखंडता और स्थिरता को बनाए रखना है, तथा यह सुनिश्चित करना है कि ग्राहकों के हितों की रक्षा की जाए।

## ECONOMY & BUSINESS

### 1. BEML मध्य प्रदेश में वंदे भारत, अमृत भारत ट्रेन कोच विनिर्माण इकाई स्थापित करेगी।

अगस्त 2025 में, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के उमरिया में वंदे भारत, अमृत भारत और मेट्रो रेल कोच सहित प्रीमियम ट्रेन कोच का उत्पादन करने के लिए भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) द्वारा एक नई विनिर्माण इकाई स्थापित करने की घोषणा की।

- **यह विनिर्माण इकाई रक्षा मंत्रालय (MoD) के अंतर्गत एक 'शेड्यूल ए' सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) के अंतर्गत स्थापित की जाएगी। यह घोषणा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने की।**

- **यह सुविधा वंदे भारत, अमृत भारत और मेट्रो रेल कोच जैसे उन्नत ट्रेन कोचों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगी, जो भारत के बढ़ते रेल बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण का समर्थन करेगी।**

- **यह इकाई मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के उमरिया में स्थित होगी, जिससे क्षेत्र की औद्योगिक और परिवहन क्षेत्र की क्षमताओं में वृद्धि होगी।**

**Key Points:-**

(i) BRAHMA (BEML रेल हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग) नामक परियोजना के तहत विनिर्माण इकाई के निर्माण के लिए कुल निवेश 1,800 करोड़ रुपये अनुमानित है।

(ii) शुरुआत में, BEML का लक्ष्य सालाना 125 से 200 रेल डिब्बों का उत्पादन करना है। उम्मीद है कि अगले पाँच वर्षों में यह उत्पादन बढ़कर सालाना 1,100 डिब्बों तक पहुँच जाएगा, जिससे भारत की रेल डिब्बा उत्पादन क्षमता मज़बूत होगी।

### 2. बीएसएनएल और एनआरएल ने रिफाइनरी क्षेत्र में उद्योग 4.0 के लिए भारत का पहला 5जी कैप्टिव गैर-सार्वजनिक नेटवर्क लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है।

3 अगस्त, 2025 को, भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) और नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (NRL) ने वित्त मंत्रालय (MoF) द्वारा आयोजित "केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) के लिए उद्योग 4.0 कार्यशाला" के दौरान गुवाहाटी, असम में एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

- **यह सहयोग एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है क्योंकि इसका उद्देश्य उन्नत औद्योगिक कनेक्टिविटी को सक्षम करने के लिए रिफाइनरी क्षेत्र में भारत का पहला 5G कैप्टिव नॉन-पब्लिक नेटवर्क (CNPN) तैनात करना है।**

- **BSNL और NRL की साझेदारी का मुख्य उद्देश्य NRL के रिफाइनरी परिचालनों के लिए समर्पित एक सुरक्षित, अति-विश्वसनीय और रीयल-टाइम 5G CNPN लागू करना है। यह नेटवर्क रिफाइनरी क्षेत्र में परिचालन दक्षता और डिजिटल परिवर्तन को बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक उद्योग 4.0 तकनीकों को एकीकृत करने हेतु एक आधारशिला के रूप में कार्य करेगा।**

- **यह पहल डिजिटल ट्विन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)-संचालित 3डी प्रिंटिंग, वर्चुअल फॉर्मूलेशन, ऑगमेंटेड रियलिटी (AR), वर्चुअल रियलिटी (VR), मिक्स्ड रियलिटी (MR), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), और बिग डेटा एनालिटिक्स सहित विभिन्न उद्योग 4.0 तकनीकों को अपनाने में सहायता करती है। इन तकनीकों से रिफाइनरी प्रक्रियाओं में क्रांतिकारी बदलाव आने और उत्पादकता एवं सुरक्षा मानकों में सुधार की उम्मीद है।**

**Key Points:-**

(i) इस परियोजना को एक अनुकरणीय मॉडल के रूप में डिजाइन किया गया है जिसे भारत भर के अन्य औद्योगिक क्षेत्रों द्वारा अपनाया जा सकता है, जिससे आधुनिकीकरण और डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा मिलेगा।

(ii) इसके अतिरिक्त, इससे रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है, विशेष रूप से भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को लाभ होगा, जो क्षेत्रीय विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित होगा।

(iii) भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत (सेल्फ-रिलायंट इंडिया) विजन और "संपूर्ण सरकार" (WoG) दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए, यह सहयोग सतत औद्योगिक विकास और डिजिटल सशक्तिकरण के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी परिनियोजन और अंतर-मंत्रालयी सहयोग के महत्व को रेखांकित करता है।

## MOUs and Agreement

**1. छत्तीसगढ़ सरकार ने 1,800 मेगावाट पंप स्टोरेज परियोजनाओं के लिए NHPC के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए।**

एनएचपीसी NHPC
A Navratna Company

छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (CSPGCL) के सहयोग से NHPC लिमिटेड (राष्ट्रीय जलविद्युत निगम लिमिटेड) के साथ कुल 1,800 मेगावाट क्षमता वाली दो पंप भंडारण परियोजनाओं (PSPs) के विकास हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण को बढ़ावा देना और ग्रिड स्थिरता सुनिश्चित करना है।

**• समझौते में दो प्रमुख PSPs का विकास शामिल है - कोरबा जिले के हसदेव बांगो में 800 मेगावाट की परियोजना, जिसकी अनुमानित लागत 3,417 करोड़ रुपये है, और कुरुंद जिले में 1,000 मेगावाट की परियोजना, जिसके लिए लगभग 6,000 करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता होगी।**

**• पंप स्टोरेज हाइड्रोपावर (PSH) एक सिद्ध बड़े पैमाने पर ऊर्जा भंडारण तकनीक है जो पानी की स्थितिज ऊर्जा के रूप में बिजली को ऊँचाई पर संग्रहीत करती है। यह प्रणाली कम व्यस्त समय के दौरान, जब बिजली की माँग कम होती है और नवीकरणीय ऊर्जा की उपलब्धता अधिक होती है, निचले जलाशय से ऊपरी जलाशय तक पानी पंप करती है।**

**• बिजली की अधिकतम मांग के समय, संग्रहित पानी को ऊपरी जलाशय से टर्बाइनों के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है, जिससे संभावित ऊर्जा पुनः बिजली में परिवर्तित हो जाती है, जिससे स्थिर बिजली आपूर्ति और ग्रिड विश्वसनीयता सुनिश्चित होती है।**

**Key Points:-**

(i) विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम, NHPC लिमिटेड, भारत का सबसे बड़ा जलविद्युत विकास संगठन है। CSPGCL के साथ सहयोग से नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण अवसंरचना में राज्य की स्थिति मज़बूत होने की उम्मीद है।

(ii) 800 मेगावाट हसदेव बांगो परियोजना कोरबा जिले के विद्युत बुनियादी ढांचे में एक रणनीतिक वृद्धि होगी, जो कोयला आधारित उत्पादन के लिए जाना जाता है, जिससे तापीय और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में संतुलन स्थापित होगा।

(iii) 1,000 मेगावाट की कुरुंद PSP छत्तीसगढ़ के नवीकरणीय ऊर्जा रोडमैप में महत्वपूर्ण योगदान देगी, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा का अधिक उपयोग, कुशल ग्रिड प्रबंधन और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी।

## App and Web Portal

### 1. नीति आयोग ने कुशल नियुक्ति के लिए 'वर्क फॉर विकसित भारत' पोर्टल लॉन्च किया।

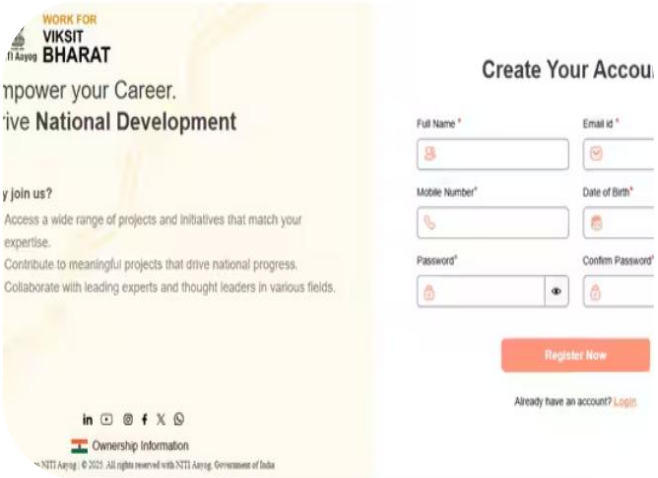


8 अगस्त, 2025 को, भारत सरकार के प्रमुख नीति थिंक टैंक, नीति आयोग ने भारत की विकास महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप विभिन्न राष्ट्रीय विकास परियोजनाओं के लिए कुशल पेशेवरों की भर्ती की सुविधा के लिए "विकसित भारत के लिए कार्य" पोर्टल लॉन्च किया।

**• workforbharat.niti.gov.in पर उपलब्ध यह पोर्टल उम्मीदवारों को पंजीकरण करने, अपनी प्रोफ़ाइल बनाने, अपनी रुचि के क्षेत्र चुनने और विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियों के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाता है। इस डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का उद्देश्य अर्थशास्त्र, बिग**

**डेटा, बुनियादी ढाँचा, जलवायु परिवर्तन, दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में प्रमुख पहलों के लिए भर्ती को सुव्यवस्थित करना है।**

**• यह कृषि नीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी बुनियादी ढाँचा, शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, और महिला एवं बाल विकास सहित नीतिगत क्षेत्रों के एक व्यापक दायरे को कवर करता है। ऐसा करके, यह व्यापक राष्ट्रीय प्रगति को लक्षित करने वाले सरकारी कार्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला का समर्थन करता है।**

**Key Points:-**

(i) इस पोर्टल का शुभारंभ श्रम और रोजगार मंत्रालय की प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) से निकटता से जुड़ा हुआ है, जिसे 1 अगस्त, 2025 को सक्रिय किया गया था।

(ii) इस योजना का लक्ष्य 31 जुलाई, 2027 तक 3.5 करोड़ नौकरियों का सृजन करना है, जिसके लिए 99,446 करोड़ रुपये का बजट परिव्यय निर्धारित किया गया है, जिसमें पहली बार काम करने वाले श्रमिकों के लिए लगभग 1.92 करोड़ नौकरियां शामिल हैं, जो समावेशी आर्थिक विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।

## IMPORTANT DAYS

### 1. विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 - 9 अगस्त को मनाया गया।

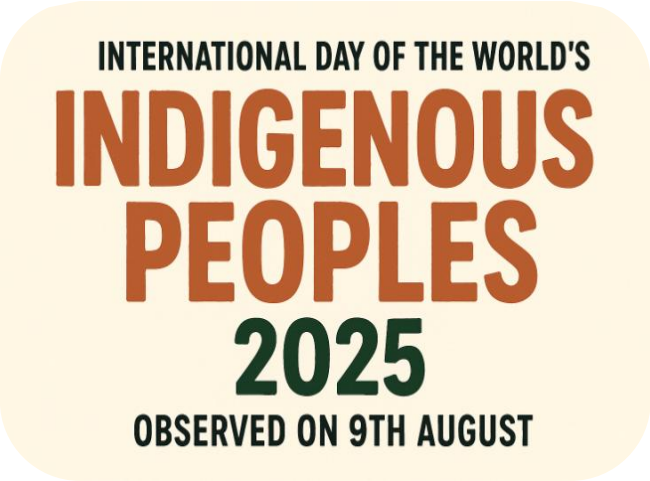


संयुक्त राष्ट्र (UN) हर साल 9 अगस्त को विश्व के आदिवासी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस (IDWIP) मनाता है ताकि आदिवासी संस्कृतियों, अधिकारों और चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। 2025 का विषय आदिवासी समुदायों पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के प्रभाव पर प्रकाश डालता है।

**• दिसंबर 1994 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संकल्प A/RES/49/214 को अपनाया, जिसके तहत 9 अगस्त को विश्व के स्वदेशी लोगों के पहले अंतर्राष्ट्रीय दशक (1995-2004) के दौरान IDWIP के रूप में घोषित किया गया।**

**• संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संकल्प A/RES/59/174 के माध्यम से 2005 से 2014 तक विश्व के स्वदेशी लोगों के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय दशक की घोषणा की, जिससे दुनिया भर में स्वदेशी अधिकारों के लिए समर्थन जारी रहा।**

**Key Points:-**

(i) IDWIP का पहला आयोजन 9 अगस्त 1995 को हुआ था, जो वैश्विक स्तर पर स्वदेशी लोगों के लिए संयुक्त राष्ट्र की औपचारिक मान्यता और प्रतिबद्धता की शुरुआत थी।

(ii) 2025 का विषय, "स्वदेशी लोग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI): अधिकारों की रक्षा, भविष्य को आकार देना", यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित है कि AI स्वदेशी अधिकारों का सम्मान करे और समावेशी

तकनीकी भविष्य को बढ़ावा दे।

(iii) IDWIP स्वदेशी पहचान, संस्कृतियों, चुनौतियों और सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी क्षेत्रों में उनके अधिकारों की रक्षा की आवश्यकता के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने का काम करता है।

## 2. भारत की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक को बढ़ावा देने के लिए 9 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस 2025 मनाया गया।

विश्व संस्कृत दिवस, जिसे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत दिवस, संस्कृत दिवस या विश्व संस्कृत दिनम के नाम से भी जाना जाता है, भारत और विश्व की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक संस्कृत के सम्मान और प्रचार हेतु प्रतिवर्ष श्रावण पूर्णिमा, हिंदू माह श्रावण की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह दिवस संस्कृत की सांस्कृतिक और भाषाई विरासत और भारतीय इतिहास एवं साहित्य में इसके महत्व पर प्रकाश डालता है।

- **विश्व संस्कृत दिवस 2025, 9 अगस्त को मनाया गया, जबकि 2024 में यह 19 अगस्त को पड़ा, और 2026 में यह 28 अगस्त को मनाया जाएगा, जो श्रावण पूर्णिमा पर आधारित चंद्र कैलेंडर समय को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, संस्कृत सीखने और प्रयोग को और प्रोत्साहित करने के लिए संस्कृत सप्ताह 2025, 6 अगस्त से 12 अगस्त तक मनाया जाएगा।**

- **विश्व संस्कृत दिवस मनाने की शुरुआत 1969 में हुई थी, जब भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने निर्देश दिया था कि संस्कृत दिवस को केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर मनाया जाए, जिससे संस्कृत भाषा की शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एक औपचारिक सरकारी पहल की स्थापना हुई।**

- **भारत सरकार द्वारा विश्व संस्कृत दिवस का पहला आधिकारिक उत्सव 1969 में मनाया गया, जो संस्कृत में रुचि को पुनर्जीवित करने और बनाए रखने के लिए एक राष्ट्रव्यापी प्रयास की शुरुआत थी, विशेष रूप से युवा पीढ़ी और विद्वानों के बीच।**

**Key Points:-**

(i) यह दिन प्राचीन संस्कृत विद्वान और व्याकरणाचार्य पाणिनि की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिनके कार्यों ने शास्त्रीय संस्कृत व्याकरण की नींव रखी। संस्कृत भाषाविज्ञान के अध्ययन और समझ के लिए उनका योगदान आज भी महत्वपूर्ण है।

(ii) संस्कृत को दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक माना जाता है और हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में इसकी समृद्ध दार्शनिक, साहित्यिक और आध्यात्मिक परंपराओं के कारण इसे "सभी भाषाओं की जननी" और "देवताओं की भाषा" के रूप में सम्मानित किया जाता है।

(iii) 2005 में, भारत सरकार ने संस्कृत को भारत की शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया और इसे भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया, जो आधिकारिक तौर पर 22 अनुसूचित भाषाओं को मान्यता देता है, जिससे इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को स्वीकार किया जाता है।

## SCIENCE AND TECHNOLOGY

### 1. स्काईरूट एयरोस्पेस ने विक्रम-1 रॉकेट के KALAM-1200 बूस्टर का स्थैतिक परीक्षण सफलतापूर्वक किया।

अगस्त 2025 में, स्काईरूट एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड (SAPL) ने KALAM-1200 सॉलिड रॉकेट मोटर का पहला स्थैतिक परीक्षण सफलतापूर्वक करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। यह मोटर विक्रम-1 प्रक्षेपण यान (LV) के पहले चरण के बूस्टर के रूप में कार्य करता है। यह परीक्षण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (SDSC) में हुआ, जो भारत की निजी क्षेत्र-आधारित अंतरिक्ष क्षमताओं के विकास में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है।

- **कलाम-1200 मोटर एक 11 मीटर लंबी, 1.7 मीटर व्यास वाली मोनोलिथिक कम्पोजिट सॉलिड रॉकेट मोटर है जिसका प्रणोदक भार 30 टन है। इसे अंतरिक्ष में 1200 किलोन्यूटन (kN) तक का अधिकतम थ्रस्ट उत्पन्न करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो विक्रम-1 प्रक्षेपण यान को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करता है।**

- **इस शक्तिशाली मोटर का नाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के सम्मान में रखा गया है, जिन्हें भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल कार्यक्रमों में उनके योगदान के लिए व्यापक रूप से 'भारत के मिसाइल मैन' के रूप में जाना जाता है।**

- **यह मोटर हाइड्रॉक्सिल-टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन (HTPB) आधारित ठोस प्रणोदक का उपयोग करती है, और दहन के दौरान होने वाली तापीय क्षति से बचाने के लिए एक उच्च-तापमान नोजल से सुसज्जित है। स्थैतिक परीक्षण का उद्देश्य उच्च दबाव में मोटर के थ्रस्ट प्रोफ़ाइल, दहन स्थिरता, नोजल की तापीय अखंडता और समग्र संरचनात्मक प्रदर्शन की जाँच करना था। यह परिचालन प्रक्षेपणों के लिए मोटर की विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है।**

**Key Points:-**

(i) कलाम-1200 का सफल परीक्षण भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुरूप है, जो निजी कंपनियों को तकनीकी अवसंरचना और प्रबंधकीय मार्गदर्शन प्रदान करके अंतरिक्ष क्षेत्र में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। स्काईरूट एयरोस्पेस की यह उपलब्धि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और प्रक्षेपण यान विकास में निजी क्षेत्र के नवाचार को बढ़ावा देने में भारत की प्रगति को रेखांकित करती है।

(ii) विक्रम-1, स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा विकसित भारत का पहला कक्षीय-श्रेणी प्रक्षेपण यान है। यह एक त्रि-चरणीय ठोस प्रणोदन प्रक्षेपण यान है जिसे छोटे उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा (LEO) में स्थापित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 2025 में प्रक्षेपण के लिए निर्धारित, विक्रम-1 अंतरिक्ष में तेज़ और माँग पर पहुँच प्रदान करता है, और सूर्य-समकालिक कक्षा (SSO) में लगभग 290 से 320 किलोग्राम और निम्न-झुकाव कक्षा (LIO) में लगभग 480 किलोग्राम पेलोड क्षमता वाले उपग्रह परिनियोजन मिशनों में सहायक है।

(iii) कलाम-1200 बूस्टर की भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि यह रॉकेट को ज़मीन से ऊपर उठाने और घने निचले वायुमंडल में गति प्रदान करने के लिए आवश्यक प्रारंभिक उच्च-प्रणोद आवेग प्रदान करता है। यह सफल स्थैतिक परीक्षण विक्रम-1 के पहले प्रक्षेपण की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो स्काईरूट

एयरोस्पेस की विश्वसनीय और कुशल प्रणोदन प्रणालियाँ बनाने की क्षमता को प्रदर्शित करता है, और भारत की निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की महत्वाकांक्षाओं को और आगे बढ़ाता है।

## BOOKS & AUTHORS

### 1. पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ अपनी पहली पुस्तक "व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स" का विमोचन करेंगे।

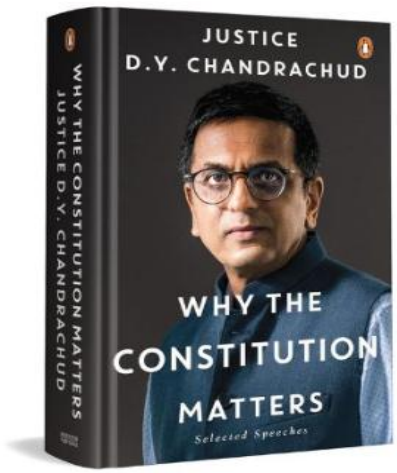


भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (CJI) न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ अगस्त 2025 तक अपनी पहली पुस्तक 'व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स' प्रकाशित करने के लिए तैयार हैं। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया (PRHI) द्वारा गुरुग्राम, हरियाणा से जारी की जाने वाली यह पुस्तक भारतीय संविधान और भारत में लोकतंत्र, न्याय, समानता और स्वतंत्रता को आकार देने में इसकी मूलभूत भूमिका पर एक गहन और व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है।

- **यह पुस्तक भारतीय संविधान की प्रासंगिकता और परिवर्तनकारी शक्ति का विस्तृत अन्वेषण प्रस्तुत करती है, तथा इसे लोकतंत्र और न्याय एवं समानता जैसे संवैधानिक मूल्यों के आधार के रूप में प्रस्तुत करती है।**

- **न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने 9 नवंबर, 2022 से 10 नवंबर, 2024 तक भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। लगभग 25 वर्षों के न्यायिक अनुभव के साथ, वे संवैधानिक मूल्यों पर विचार करने के लिए अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करते हैं।**

- **पुस्तक में असहमति का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, गोपनीयता, लैंगिक समानता, विकलांगता अधिकार और पर्यावरण न्याय जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई है, जिसमें ऐतिहासिक निर्णय भी शामिल हैं जो संविधान के वास्तविक जीवन पर प्रभाव को दर्शाते हैं।**

**Key Points:-**

(i) पुस्तक का एक उद्देश्य जटिल कानूनी अवधारणाओं को सरल बनाना है ताकि अधिक नागरिक सहभागिता को बढ़ावा मिले और भारत के संवैधानिक ढांचे के बारे में जनता की समझ बढ़े।

(ii) यह कृति न्यायिक संस्मरण और कार्रवाई का आह्वान दोनों है, जो नागरिकों से लोकतांत्रिक सिद्धांतों और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने का आग्रह करती है।

(iii) गुरुग्राम, हरियाणा स्थित पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक का उद्देश्य भारत के संवैधानिक मूल्यों के साथ जनता की सहभागिता को बढ़ावा देना तथा जागरूक नागरिकों को प्रोत्साहित करना है।

## Static GK

| | | |
|---|---|---|
| **the United Nations Development Programme (UNDP)** | प्रशासक : अचिम स्टेनर | मुख्यालय : न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) |
| **the Ministry of Heavy Industries (MHI)** | केंद्रीय मंत्री: एच. डी. कुमारस्वामी | मुख्यालय: नई दिल्ली |
| **Madhya Prades** | राज्यपाल: मंगूभाई सी. पटेल | राजधानी: भोपाल |
| **MeitY** | मंत्री: अश्विनी वैष्णव | मुख्यालय: नई दिल्ली |
| **Skyroot Aerospace Private Limited** | मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) : पवन कुमार चंदना | मुख्यालय : हैदराबाद, तेलंगाना |
| **Assam** | मुख्यमंत्री: हिमंत बिस्वा सरमा | राज्यपाल: लक्ष्मण आचार्य |
| **National Hydroelectric Power Corporation (NHPC) Limited** | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक: श्री राज कुमार चौधरी | मुख्यालय: फ़रीदाबाद |
| **the Department of Administrative Reforms and Public Grievances (DARPG)** | सचिव : वी श्रीनिवास | मुख्यालय: नई दिल्ली |
| **NITI Aayog** | CEO : बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम | मुख्यालय: नई दिल्ली |
| **RBI** | राज्यपाल: संजय मल्होत्रा | मुख्यालय: मुंबई |